अपराह्न 12.01 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका की हाल की राजकीय यात्रा

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अमेरिका के अपने हाल के दौरे के संबंध में एक वक्तव्य इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। राष्ट्रपति श्री जार्ज बुश ने मुझे सरकारी दौरे पर आमंत्रित किया था। वहां पर मेरा और मेरी पत्नी का राष्ट्रपति श्री बुश तथा प्रथम महिला श्रीमती लॉरा बुश द्वारा गर्मजोशी एवं सम्मान के साथ स्वागत किया गया। राष्ट्रपति श्री बुश के साथ हुई मेरी व्यापक बातचीत में अनेक द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों को शामिल किया गया। अमेरिका प्रवास के दौरान मेरी उप राष्ट्रपति तथा अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ मंत्रिमंडल सदस्यों जैसे विदेश मंत्री सुश्री कोंडोलीजा राइस, रक्षा मंत्री श्री रम्सफील्ड तथा वित्त मंत्री श्री स्नो से भी मुलाकात हुई। मुझे अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं समझता हूं कि मेरा यह दौरा हमारी विदेश नीति से जुड़े हितों को आगे बढ़ाने में और इसके सार्थक नतीजों को देखते हुए सफल रहा है। यह इस बात से स्पष्ट है कि अमेरिका यह संकेत देना चाहता था कि हमने अपने संबंधों में बदलाव लाने शुरू कर दिए हैं ताकि उनमें निहित संभाव्यता को ठोस रूप दिया जा सके।

मेरे दौरे के दौरान जारी किये गए संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी जा रही है। महोदय, मेरे दौरे का प्रयोजन अमेरिकी सरकार को भारत में सन् 1991 से शुरू हुए बदलावों की जानकारी देना था। इन परिवर्तनों से हमें अमेरिका के साथ और अधिक समानता के आधार पर कार्य करने की एक अधिक मजबूत क्षमता हासिल हुई हैं क्योंकि हमारे दोनों देशों के समक्ष समान चिन्ताएं और चुनौतियां हैं। मैंने इस बात पर भी बल दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत है और हम आशा करते हैं कि हम वैश्वीकरण की आर्थिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेंगे और उनसे लाभ उठायेंगे। हम इस बात के लिए कृत-संकल्प है कि हम निवेश जिसमें विदेशी निवेश भी शामिल है, के लिए एक आकर्षक केन्द्र के रूप में उभरें और अमेरिका का व्यवसायी समुदाय अधिक से अधिक निवेश तथा व्यापार के जरिए भारत के विकास में अपना योगदान दे सके। हमने ऐसे परस्पर लाभकारी संबंधों की शुरुआत कर ली है जिनका स्वरूप हमारे ज्ञान क्षेत्र की मजबूती पर तय किया गया है। इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य अमेरिका को यह स्पष्ट कराना था कि भारत ज्ञान-आधारित उद्योगों और सेवाओं के एक केन्द्र के रूप में उभरने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच दीर्घकालिक सहयोग का एक बेहतर आधार तैयार होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार और हमारी विकास दरों में वृद्धि न केवल हमारे अपने लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था की प्रगति और स्थिरता के लिए भी लाभदायक होंगी।

वाशिंगटन में राष्ट्रपति श्री बुश और उनके प्रशासन के सदस्यों से हुई मेरी बातचीत उपयोगी रहीं और इनसे इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिली है। दोनों पक्ष इस बात से सहमत थे कि हमारे संबंध साझे मूल्यों और उन साझे हितों पर आधारित हैं जिनमें लोकतांत्रिक क्षमताओं को अपेक्षानुसार और स्वेच्छा से मजबूत करना तथा दोहरा मापदंड अपनाए बगैर आतंकवाद से मुकाबला करना शामिल है। भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने के मुद्दे को दोनों देशों द्वारा एक प्राथमिकता समझा गया। आर्थिक मोर्चे पर हमने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सी.ई.ओ.) का मंच शुरू करने का स्वागत किया जिसने दोनों देशों के सर्वोत्तम व्यावसायियों को एक-दूसरे के करीब लाने में मदद की है। हमने भारत के आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत् विकास में इसके महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेशों की हमारी जरूरत पर बातचीत की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्व को समझते हुए हम कृषि क्षेत्र में पहल करने पर भी सहमत हुए जिसका उद्देश्य हरित क्रांति के आधार पर अनुसंधान और कृषि पद्धतियों की एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना है।

महोदय, भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व को समझते हुए हमने उन उपायों पर भी चर्चा की जो यह सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिका की उच्च प्रौद्योगिकी तक सुलभता अधिक उदार और पूर्वानुमेय हो। हम अंतरिक्ष में खोज, उपग्रह संचालन तथा प्रक्षेपण जैसे अग्रणी क्षेत्रों, और उनसे संबंधित वाणिज्यिक कार्यकलापों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के प्रयास करेंगे जिनसे हमारे अंतरिक्ष उद्योग जिसे एक ग्लोबल लीडर के रूप में जाना जाता है, को बहुत अधिक लाभ होगा। मेरी यात्रा के दौरान एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी ढांचागत समझौते पर भी सहमति हुई है जिसमें संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण के विस्तार की व्यवस्था होगी। सहयोग के एक नए स्तर पर कार्य करने के आशय को रेखांकित करते हुए अमेरिका ने अपनी *एन्टिटी लिस्ट* से पांच भारतीय संगठनों को हटाने की घोषणा की।

अपराह्न 12.01 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका की हाल की राजकीय यात्रा

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अमेरिका के अपने हाल के दौरे के संबंध में एक वक्तव्य इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। राष्ट्रपति श्री जार्ज बुश ने मुझे सरकारी दौरे पर आमंत्रित किया था। वहां पर मेरा और मेरी पत्नी का राष्ट्रपति श्री बुश तथा प्रथम महिला श्रीमती लॉरा बुश द्वारा गर्मजोशी एवं सम्मान के साथ स्वागत किया गया। राष्ट्रपति श्री बुश के साथ हुई मेरी व्यापक बातचीत में अनेक द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों को शामिल किया गया। अमेरिका प्रवास के दौरान मेरी उप राष्ट्रपति तथा अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ मंत्रिमंडल सदस्यों जैसे विदेश मंत्री सुश्री कोंडोलीजा राइस, रक्षा मंत्री श्री रम्सफील्ड तथा वित्त मंत्री श्री स्नो से भी मुलाकात हुई। मुझे अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं समझता हूं कि मेरा यह दौरा हमारी विदेश नीति से जुड़े हितों को आगे बढ़ाने में और इसके सार्थक नतीजों को देखते हुए सफल रहा है। यह इस बात से स्पष्ट है कि अमेरिका यह संकेत देना चाहता था कि हमने अपने संबंधों में बदलाव लाने शुरू कर दिए हैं ताकि उनमें निहित संभाव्यता को ठोस रूप दिया जा सके।

मेरे दौरे के दौरान जारी किये गए संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी जा रही है। महोदय, मेरे दौरे का प्रयोजन अमेरिकी सरकार को भारत में सन् 1991 से शुरू हुए बदलावों की जानकारी देना था। इन परिवर्तनों से हमें अमेरिका के साथ और अधिक समानता के आधार पर कार्य करने की एक अधिक मजबूत क्षमता हासिल हुई है क्योंकि हमारे दोनों देशों के समक्ष समान चिन्ताएं और चुनौतियां हैं। मैंने इस बात पर भी बल दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत है और हम आशा करते है कि हम वैश्वीकरण की आर्थिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेंगे और उनसे लाभ उठायेंगे। हम इस बात के लिए कृत-संकल्प हैं कि हम निवेश जिसमें विदेशी निवेश भी शामिल है, के लिए एक आकर्षक केन्द्र के रूप में उभरें और अमेरिका का व्यवसायी समुदाय अधिक से अधिक निवेश तथा व्यापार के जरिए भारत के विकास में अपना योगदान दे सके। हमने ऐसे परस्पर लाभकारी संबंधों की शुरुआत कर ली है जिनका स्वरूप हमारे ज्ञान क्षेत्र की मजबूती पर तय किया गया है। इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य अमेरिका को यह स्पष्ट कराना था कि भारत के ज्ञान-आधारित उद्योगों और सेवाओं के एक केन्द्र के रूप में उभरने से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच दीर्घकालिक सहयोग का एक बेहतर आधार तैयार होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार और हमारी विकास दरों में वृद्धि न केवल हमारे अपने लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था की प्रगति और स्थिरता के लिए भी लाभदायक होंगी।

वाशिंगटन में राष्ट्रपति श्री बुश और उनके प्रशासन के सदस्यों से हुई मेरी बातचीत उपयोगी रहीं और इनसे इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिली है। दोनों पक्ष इस बात से सहमत थे कि हमारे संबंध साझे मूल्यों और उन साझे हितों पर आधारित हैं जिनमें लोकतांत्रिक क्षमताओं को अपेक्षानुसार और स्वेच्छा से मजबूत करना तथा दोहरा मापदंड अपनाए बगैर आतंकवाद से मुकाबला करना शामिल है। भारत द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने के मुद्दे को दोनों देशों द्वारा एक प्राथमिकता समझा गया। आर्थिक मोर्चे पर हमने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सी.ई.ओ.) का मंच शुरू करने का स्वागत किया जिसने दोनों देशों के सर्वोत्तम व्यावसायियों को एक-दूसरे के करीब लाने में मदद की है। हमने भारत के आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत् विकास में इसके महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेशों की हमारी जरूरत पर बातचीत की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्व को समझते हुए हम कृषि क्षेत्र में पहल करने पर भी सहमत हुए जिसका उद्देश्य हरित क्रांति के आधार पर अनुसंधान और कृषि पद्धतियों की एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना है।

महोदय, भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व को समझते हुए हमने उन उपायों पर भी चर्चा की जो यह सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिका की उच्च प्रौद्योगिकी तक सुलभता अधिक उदार और पूर्वानुमेय हो। हम अंतरिक्ष में खोज, उपग्रह संचालन तथा प्रक्षेपण जैसे अग्रणी क्षेत्रों, और उनसे संबंधित वाणिज्यिक कार्यकलापों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के प्रयास करेंगे जिनसे हमारे अंतरिक्ष उद्योग जिसे एक ग्लोबल लीडर के रूप में जाना जाता है, को बहुत अधिक लाभ होगा। मेरी यात्रा के दौरान एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी ढांचागत समझौते पर भी सहमति हुई है जिसमें संयुक्त अनुसंधान और प्रशिक्षण के विस्तार की व्यवस्था होगी। सहयोग के एक नए स्तर पर कार्य करने के आशय को रेखांकित करते हुए अमेरिका ने अपनी *एन्टिटी लिस्ट* से पांच भारतीय संगठनों को हटाने की घोषणा की।

इनमें से तीन अन्तरिक्ष क्षेत्र से तथा दो आणविक ऊर्जा क्षेत्र से हैं। अमेरिका ने इस मामले में आगे समीक्षा करने का भी संकेत दिया।

अध्यक्ष महोदय, विकास के लिए हमारे दृष्टिकोण के एक आवश्यक घटक के रूप में भारत की ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत मेरी बातचीत का एक महत्वपूर्ण विषय था। मैंने इस बात की भी जानकारी दी कि भारत की आर्थिक विकास दर को बनाए रखने और उसमें तेजी लाने के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि परमाणु ऊर्जा सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों तक भारत की बेरोकटोक पहुंच हो। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका ने सभी स्रोतों से ऊर्जा की पर्याप्त और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के बारे में हमारे पक्ष को समझा। मैंने उल्लेख किया कि इस दृष्टिकोण से जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होने में मदद मिलेगी। इसके दोहरे लाभ होंगे - एक तो तेल कीमतों में कमी आएगी तथा साथ ही पर्यावरण को भी अक्षुण्ण बनाए रखा जा सकेगा। इस संदर्भ में हमने असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

तद्नुसार, राष्ट्रपति श्री बुश के साथ मेरी बातचीत का केन्द्र-बिन्दु भारत और अमेरिका के बीच उस द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहयोग को फिर से शुरू करना था जिसमें दशकों से प्रगति नहीं हुई थी। राष्ट्रपति बुश और मैं इस बात पर सहमत हुए कि हम परमाणु ऊर्जा को भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के एक साधन के रूप में संवर्धित करने की दिशा में काम करेंगे। अमेरिकी पक्ष ने अपने कानूनों और नीतियों में घरेलू स्तर पर सामंजस्य स्थापित करने और प्रासंगिक अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने हेतु अपने दोस्तों और साझेदारों के साथ मिलकर काम करने का वायदा किया। सम्पूर्ण असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग में तारापुर संयंत्र के लिए ईंधन की आपूर्ति पर शीघ्रता से विचार करना शामिल होगा लेकिन यह उस तक ही सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका अपने अन्य भागीदारों को भी इस प्रकार के अनुरोधों पर अनुकूल ढंग से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हमने अन्तरराष्ट्रीय ताप परमाणु अनुसंधान परियोजना और जेनेरेशन IV इंटरनेशनल फोरम में पूर्ण सहयोगी के रूप में भाग लेने की अपनी इच्छा पर विचार करवाने में भी सफलता पाई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों का भविष्य में हमारे देश के लिए और वास्तव में विश्व ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्व है। अमेरिका ने भारत को शामिल करने के विचार से अन्य सहभागियों से विचार-विमर्श करने पर भी सहमति जताई। यह न केवल हमारे परमाणु वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त की गई अत्यधिक अन्तरराष्ट्रीय महत्ता और मान-सम्मान का ही सबूत है बल्कि उनकी उपलब्धियों की पहचान का प्रमाण भी है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा परमाणु कार्यक्रम बेजोड़ है। इसमें सभी प्रकार के कार्यकलाप शामिल है जो विद्युत उत्पादन, उच्च अनुसंधान तथा विकास और हमारे स्ट्रैटेजिक कार्यक्रम सहित उन्नत परमाणु ऊर्जा की विशेषता दर्शाते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने सम्पूर्ण परमाणु ईंधन चक्र पर विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। हमने अपने कार्यक्रम के विकास का जो तरीका सोचा है वह हमारे सीमित यूरेनियम संसाधनों और थोरियम के विशाल भंडार पर आधारित है। यद्यपि इन संसाधनों में उपलब्ध ऊर्जा क्षमता असीम है तथापि, इस त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जिसमें पहले स्तर पर प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स (पी.एच.डब्ल्यू.आर.), दूसरे स्तर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स और तीसरे स्तर पर थोरियम रिएक्टर्स होते हैं, के प्रति वचनबद्ध रहते हैं। इनके लिए एक समन्वित और क्रमिक ढंग से कार्यान्वयन की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है और हम पं. जवाहर लाल नेहरू और डॉ. होमी भाभा की भावी सोच के अनुसार इस कार्यक्रम में अच्छी प्रगति कर रहे है। हम इस मूल्यवान विरासत को आगे बढ़ाते रहेंगे।

महोदय, ऊर्जा हमारे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। हमने अपने दीर्घकालिक ऊर्जा स्रोतों का आकलन किया है और यह स्पष्ट है कि परमाणु विद्युत को हमारी बिजली उत्पादन योजनाओं में एक अहम भूमिका अदा करनी हैं। यद्यपि घरेलू संसाधनों पर आधारित हमारे देशी परमाणु विद्युत कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का विकास जारी रहेगा फिर भी, हमारे लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन को तेजी से आगे बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। हम न्यूनतम संभव लागत पर प्राप्त किए गए आर्थिक विकास के स्तरों पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से यह बहुत उपयोगी होगा यदि हम अन्तरराष्ट्रीय बाजार से परमाणु ईंधन के साथ-साथ परमाणु रिएक्टर्स भी प्राप्त कर सकें। इस समय, हमारे चारों ओर परमाणु प्रौद्योगिकी प्रतिबंधक व्यवस्थाएं लागू होने के कारण यह संभव नहीं है। हम अमेरिका के साथ अब जिस बात पर सहमत हुए है उससे हमारे घरेलू प्रयासों में मदद देने के लिए बाहर से परमाणु ईंधन तथा परमाणु विद्युत रिएक्टर्स और अन्य प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने की संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। कार्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन से विश्व में हो रहे जलवायु परिवर्तन के संबंध में भी काफी चिंता है। इस प्रकार हमें स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां अपनाने की जरूरत है। इस संदर्भ में भी परमाणु विद्युत अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महोदय, संयुक्त वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया है कि उन्नत किस्म की परमाणु प्रौद्योगिकी से संपन्न एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते भारत को वही लाभ तथा फायदे मिलने चाहिएं जो

[डा. मनमोहन सिंह]

ऐसे अन्य देशों को मिलते है। इसके परिणामस्वरूप, हम यह आशा करते हैं कि अमेरिका तथा दुनिया के देशों के साथ भारत की परमाणु व्यापार तथा वाणिज्य की पुनः शुरुआत एक ऐसा लक्ष्य है जो हासिल किया जा सकता है तथा इसमें प्रौद्योगिकीय प्रतिबंधक व्यवस्थाओं जिन्होंने अब तक भारत को निशाना बनाया हुआ है, को समाप्त करना भी शामिल है।

अन्य परमाणु शक्ति-सम्पन्न देशों के समान ही लाभ तथा फायदे हासिल करने के पीछे हमारी यह सोच है कि हम भी अमेरिका सहित ऐसे अन्य परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों की भांति बन्धनों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। साथ ही हम भी वैसे ही अधिकारों तथा लाभों की आशा करते हैं। इस तरह हमने गैर भेदभाव का सिद्धान्त सुनिश्चित किया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी प्रतिबद्धताएं अमेरिका द्वारा अपनी ओर से इस समझौते को पूरा करने पर निर्भर करेंगी और तभी हम भी अपनी ओर से इसे पूरा करेंगे। संयुक्त वक्तव्य में हमारे द्वारा असैन्य तथा सैन्य परमाणु सुविधाओं की चरणबद्ध तरीके से पहचान करने और उन्हें अलग करने तथा असैन्य परमाणु सुविधाओं को स्वेच्छा से अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों के तहत रखने हेतु निर्णय लेने की बात कही गई है। भारत कभी भी भेदभाव स्वीकार नहीं करेगा। इस संयुक्त वक्तव्य में हमारे स्ट्रैटेजिक परमाणु अस्त्र कार्यक्रम, जिस पर हम अपना अप्रतिबंधित, पूर्ण तथा स्वायत्त नियंत्रण बनाए रखेंगे, को सीमित करने या उस पर रोक लगाने जैसा कुछ नहीं है।

संयुक्त वक्तव्य में उल्लिखित सभी उपायों के कार्यान्वयन की कुंजी पारस्परिकता है। हम अमेरिका तथा भारत द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों के बीच घनिष्ठ सह-सम्बंधों की अपेक्षा करते हैं। भारत की कार्रवाइयां हर स्तर पर अन्य पक्ष द्वारा पूरी की गई कार्रवाइयों पर निर्भर करेगी। यदि हम इस बात से संतुष्ट नहीं हुए कि हमारे हित पूर्णतः सुरक्षित हैं तो हम पूर्व-निर्धारित तरीके से आगे बढ़ने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

अतः हमारे अपने विधिवत् सुविचारित राष्ट्रीय निर्णयों के आधार पर असैन्य परमाणु सुविधाओं की पहचान तथा उन्हें अलग करने के सम्बंध में चरणबद्ध कार्रवाई यथोचित समय पर और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। हमारी असैन्य सुविधाओं को स्वैच्छिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों के तहत रखने से पूर्व हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत पर लगे सभी प्रतिबंध उठा लिए गए हैं। निर्णय लेने की हमारी स्वायत्तता किसी भी हालत में सीमित नहीं होगी।

मैं सदन में जोर देकर यह बात कहना चाहता हू कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति सम्पन्न देश है जिसका परमाणु अप्रसार के सम्बंध में त्रुटिहीन रिकार्ड रहा है। हमारी स्ट्रैटेजिक नीतियां तथा परिसम्पत्तियां राष्ट्रीय सुरक्षा का स्रोत हैं और बनी रहेंगी तथा ये किन्हीं भी बाहरी वार्ताकारों के साथ हमारी बातचीत के दायरे से बाहर रहेंगी। इस अवसर पर मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार मौजूदा अथवा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे स्ट्रैटेजिक कार्यक्रम के सम्बंध में किसी भी विखंड्य सामग्री की कमी नहीं होने देगी अथवा किसी भी अन्य सामग्री पर सीमा बंधन नहीं लगने देगी। हमारे देश के रक्षा तथा सुरक्षा हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और बने रहेंगे।

हमारी नीतियों तथा कार्यों के कारण हमें विश्व में पहचान तथा व्यापक सम्मान मिला है जोकि मुझे विश्वास है यह सदन भी मानता है और उसका स्वागत करता है। इसके कारण हम न केवल तीन दशक से चले आ रहे प्रौद्योगिकीय प्रतिबंधन को समाप्त करने के लिए एक विश्वसनीय उदाहरण बन गए हैं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में हमें एक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त होने लगा है।

महोदय, मैंने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान उस तथ्य पर भी प्रकाश डाला जिसके आधार पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का विस्तार करने के लिए और परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश पाने के लिए एक ठोस मामला तैयार किया है। इस मसले पर अमेरिका का बिलकुल अलग रुख है और उसने भारत के रुख का समर्थन करना संभव नहीं पाया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि समय के साथ-साथ अमेरिका हमारी बात को वैधता प्रदान करेगा। वस्तुतः संयुक्त वक्तव्य में भारत के रुख के प्रति अमेरिका की बढ़ती मान्यता परिलक्षित होती है। इसमें उल्लेख किया गया है कि "अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को विश्व परिदृश्य में सन् 1945 से लेकर अब तक हुए बदलावों को पूर्णतया प्रतिबिम्बित करना होगा।" अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी यह बात दोहराई है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भारत की प्रमुख तथा बढ़ती भूमिका को परिलक्षित करने के प्रति अपना अनुकूल रवैया अपनाने लगी हैं। इस संबंध में, अमेरिका के साथ मिलकर हमने जो वैश्विक पहलें आरंभ की हैं, वे हमारी सुदृढ़ता तथा क्षमताओं को अधिक मान्यता देने की साक्ष्य हैं। इन पहलों में आपदा राहत, एच.आई.वी./एड्स तथा उन समाजों जो इस तरह की सहायता चाहते हैं, में लोकतांत्रिक क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं मानता हूं कि मेरी अमेरिका यात्रा से हमारी चिन्ताओं और हितों को बेहतर ढंग से समझा गया है। इस यात्रा के कारण महत्वपूर्ण पहलें हुई हैं जिनका भारत के लिए अत्यधिक आर्थिक तथा विकास सम्बंधी महत्व है। मैंने भारत की जनता की ओर से मजबूत पक्ष रखा है कि जब भी वैश्विक परिषदों में ऐसे निर्मय लिए जाएं जिनसे हम प्रभावित होते हैं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह सदन इन सभी बातों का स्वागत करेगा।

महोदय, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हम इस बात को लेकर गर्व महसूस कर सकते हैं कि हमारी उपलब्धियों को दुनियाभर में स्वीकार किया जा रहा है। इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, शिक्षकों, कामगारों, किसानों, उद्यमियों तथा व्यावसायिकों को जाता है। भारत अब सौ करोड़ से भी अधिक की जनसंख्या वाला देश है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जिसका आज सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) वृद्धि दर में दूसरा स्थान है। जिस तरह से हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में यह प्रगति की है, वह प्रशंसा और सम्मान की बात है। भारत को विश्व में निरंतर एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। इसलिए, मैं मानता हूं कि हमारी शक्ति हमारे द्वारा चुने गए सही मार्ग में और हमारे लोगों की सृजनात्मकता तथा उद्यमशीलता में निहित है। इससे आज भारत राष्ट्रों के बीच गर्व से खड़ा होने में समर्थ हुआ है।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि संयुक्त वक्तव्य के पहलुओं के संबंध में कुछ हलकों में आलोचना होगी। रचनात्मक आलोचना संसदीय परम्परा का हिस्सा है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इससे हमारी चर्चाओं में स्पष्टता और हमारी लोकतंत्रीय संस्था में जीवंतता आती है। तथापि, मैं इस सम्माननीय सदन को तथा इसके माध्यम से अपने राष्ट्र को आश्वस्त कर सकता हूं कि अमेरिका का मेरा दौरा विश्व की एक महाशक्ति के साथ संबंध बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया था ताकि हम अपने विकास संबंधी विकल्पों को व्यापक बना सकें। मेरा प्रयास था कि अपने स्ट्रैटेजिक हितों की रक्षा करते हुए अपने विकास को बढ़ाने के लिए ऊर्जा आपूर्तियां प्राप्त की जाएं। मैं समझता हूं कि लम्बे समय से चली आ रही कुछ प्रतिबंधात्मक परमाणु व्यवस्थाओं को हटाने से अब हमें काफी मात्रा में ऊर्जा मिल सकेगी जिसकी हमें अपने औद्योगिकीकरण कार्यक्रम के व्यापक विकास के लिए जरूरत होगी। एक बार परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाने पर यह सस्ती ऊर्जा भारत को आर्थिक वृद्धि की अपनी मौजूदा गति को तेज करने में सक्षम बना देगी ताकि भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित बनाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्माननीय सदन में एकत्रित हम सभी लोग यह मानते हैं कि हमने अपने स्वतंत्रता संघर्ष से प्रेरित होकर विरासत में एक गौरवशाली और देशभक्तिपूर्ण परम्परा पाई है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा समर्थित वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए काम करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारा मुख्य ध्येय रहेगा। साथ ही, मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि जहां तक हमारी मौलिक तथा स्ट्रैटेजिक जरूरतों का संबंध है, हमने न तो कभी समझौता किया है और न ही कभी समझौता करेंगे। हमारी विरासत हममें विश्वास जगाती है, हमारा अनुभव हमें साहस प्रदान करता है और हमारी मान्यता हमें आज अधिकारपूर्वक यह दावा करने का दृढ़ विश्वास दिलाती है कि हमारा राष्ट्र एक अधिक बेहतर भविष्य की दहलीज पर खड़ा है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे अमेरिका दौरे से हमारी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु नए अवसरों तथा संभावनाओं के द्वार खुले हैं और तीव्र सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। हमें इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक संगठित राष्ट्र के रूप में मिल-जुलकर कार्य करना होगा ताकि भारत को उभरती विश्व अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख शक्ति-केंद्र बनाया जा सके।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2384/05]

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, मैं आशा करता हूं कि इसे चर्चा में बदला जाएगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सूचनाएं दीजिए। सोमवार को ही प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री उपस्थित होंगे। अत: माननीय सदस्य सूचनाएं दे सकते हैं, सोमवार को ही इस पर चर्चा की अनुमति दूंगा।

अपराह्न 12.26 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा के कार्य के बारे में

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को सूचित करना है कि 24 जुलाई, 2005 को हुई नेताओं की बैठक में यह सहमति व्यक्त की गई कि प्रश्नकाल के पश्चात् उठाए जाने वाले अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को चरणबद्ध तरीके से लिया जाए। पहले चरण में, प्रश्नकाल के पश्चात् अत्यंत अविलंबनीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामान्यत: लगभग पांच मामले